रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

ः आयुक्त (अपील -।) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शूल्क, :

ः सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :

: आंबावाडी, अहमदाबाद— 380015. :

| | ः आबावाडा, अहम | दाबाद— 380015. : | 4228 |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------|
| क क | फाइल संख्या : File No : V2(70)21/Ah | | 52M to |

V W अपील आदेश संख्या :Order-In-Appeal No.: <u>AHM-EXCUS-003-APP-191-16-17</u> ख

दिनाँक Date : <u>22.12.2016</u> जारी करने की तारीख Date of Issue____|

<u>श्री उमाशंकर</u> आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-I)Ahmedabad

_ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-। आयुक्तालय द्वारा जारी मूल ग दिनाँकः से सुजित आदेश सं

Arising out of Order-in-Original: 10/DC/DEM/CEX/2015-16 Date: 19.02.2016 Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kadi, A'bad-III.

अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता ध

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Gemstone Glass Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन ः

Revision application to Government of India :

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में (1)पूर्वाक्त धारा को उप–धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप[ॅ]भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने (ii) में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a (ii) warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क (ख) कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्योतित 割日

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside (b) India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

- यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया (ग) माल हो।
- In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of (C) duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए–8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल–आदेश एवं अपील आदेश की दो–दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35–इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर–6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/– फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/– की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीलः— Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35– ण्वबी/35–इ के अंतर्गत:–

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉंक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण <u>(सिस्टेट)</u> की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ–20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद–380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपन्न इ.ए–3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 1000/– फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001-and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs. 10,000/- and Rs. 10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Eac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall beer a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-l item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३७फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनांक: ०६.०८.२०१४ जो की वित्तीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " मॉंग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

 \rightarrow Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस s.dwR me..इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been filed by M/s Gemstone Glass Pvt Ltd., Plot No.23/E, GIDC Estate, Kadi, Mehsana, Gujarat (hereinafter referred to as "the appellant") against Order-in-Original No.10/DC/DEM/CEx/2015-16 dated 19.02.2016 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Deputy Commissioner of Central Excise, Kadi Division (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Briefly stated, the facts of the case is that during the course of audit of the records of the appellant, it was noticed that they had wrongly availed [1] Cenvat Credit amounting to Rs.2,77,850/- on Rent-A-Cab during the period from March 2011 to March 2015; and [2] Cenvat credit amounting to Rs.11,944/- towards purchase of Steel Wire Conveyor Belt during February 2015. The appellant has paid the Cenvat credit wrongly availed on Rent-A-Cab with interest and Credit wrongly availed on purchase of Steel Wire Conveyor Belt on 22.06.2015. A show cause notice dated 30.11.2015 was issued to the appellant for [1] demanding and appropriating of Cenvat Credit paid with interest; [2] interest not paid on the amount of Rs.11,944/-; and [3] imposition of penalty under provisions of Section 11 AC(1)(c) of the Central Excise Act, 1944, read with Rule 15(2) of Cenvat Credit Rules, 2004. The said show cause notice was adjudicated, vide the impugned order. The adjudicating has confirmed the demand of duty with interest in respect of Cenvat Credit wrongly availed on Rent-A-Cab and imposed penalty an dropped the demand in respect of Cenvat credit wrongly availed on Steel Wire Coveyor Belt.

3. Being aggrieved, the appellant has filed the present appeal on the grounds that the disputed amount was paid with interest before issuance of show cause notice, hence no penalty under Section 11 AC is imposable in terms of Section 11 A(2) of CEA; that as per provisions of Section AC(1) (a) if the duty with interest has been paid prior to issuance of show cause notice or within 30 days from the issuance of show cause notice, no penalty is payable and the proceedings in respect of duty and interest so paid are deemed to be concluded; that the credit in dispute was allowed to be taken vide law interpreted in the case of Stanzen Toyoyetzu (I) Pvt Ltd-2011(23) STR 44 and M/s Tata Auto Comp System Ltd -2012(277) ELT.

4. A personal hearing in the matter was held on 20.12.2016. Ms Pooja Shah, C.A, appeared for the same and submitted that no penalty is levied in the matter.

5. I have gone through the facts of the case, submissions made in the appeal memorandum as well as at the time of personal hearing. The issue involved in the matter is relating to confirmation of Cenvat credit amounting to Rs.2,77,850/ wrongly availed by the appellant on Rent-A-Cab service and imposition of penalty amounting to Rs.1,38,925/- by the adjudicating authority.

6. In the instant case, I observe that the appellant is, however, not disputing the amount of Rs.2,77,850/- with interest paid by them; that they only disputes the amount of Rs.1,38,925/- imposed as penalty. Therefore, I limit the discussion with regard to imposition of penalty only.

F No.V2(70)21/Ahd-III/16-17/A.I

The appellant argued that they have paid the demand with interest in question before 7. issuance of show cause notice and hence no penalty is imposable in terms of provisions of Section 11 A(2) and amended Section 11AC (1) (a) of CEA. The said argument is not acceptable. Both the Sections *ibid* refers the case where duty of excise has not been paid or has been short levied/paid other than the reasons of fraud or collusion or any willful mis-statement or suppression of facts or contravention of any of the provisions the Act or Rule with intent to evade payment of duty. From the facts of the case, I observe that the instant case is different from the situation as specified in the said Sections. In the instant case, the appellant had taken the credit in dispute for the period from March 2011 to March 2015, though the definition of "input service" credit under Rule 2(1) of CER clearly denies the credit of service tax paid on rent-a cab service to the appellant. The exclusion provision (B) of 2(1) of CER states that "service provided by way of renting of a motor vehicle, in so far as they relate to a motor vehicle which is not a capital goods". In the circumstances, taking credit on inadmissible input service clearly indicates the intention of evading duty. Further, the onus of taking legitimate Cenvat credit has been cast on the appellant in the self-assessment era. Therefore, the obligation of taking correct credit is cast on the part of the appellant. When the definition of input service denies the credit of Rent-A-Cab service, availment of such credit itself leads a situation of evasion of duty by willful misstatement and suppression of facts. Further, in the instance case, it is fact that the department has come to know that the appellant had taken such credit only after the records were audited.

\$5 ···· **

8. Further, the appellant argued that that the credit in dispute was allowed to be taken vide law interpreted in the case of Stanzen Toyoyetzu (I) Pvt Ltd-2011(23) STR 44 and M/s Tata Auto Comp System Ltd -2012(277) ELT. I observe that the said cases are pertaining to period prior to the amendment of clause (B) of Rule 2(l) of CER w.e.f 01.07.2012. Therefore, the said argument is also not justifiable and acceptable.

9. In view of above discussion, I hold that the adjudicating authority has rightly invoked extended period of limitation and imposed penalty under Section 11 AC(e) of CEA read with Rule 15(2) of CER is appear to be apt in the light of the circumstances of the case. Therefore, I reject the appeal filed by the appellant.

(उमा शंकर) आयुक्त (अपील्स - I) Date: 22/12/2016



Attested (Mohanan V.V) Superintendent (Appeal-I) Central Excise, Ahmedabad

BY R.P.A.D. To, M/s Gemstone Glass Pvt Ltd., Plot No.23/E, GIDC Estate, Kadi, Mehsana, Gujarat Copy to:-

The Chief Commissioner of Central Excise, Ahmedabad.
The Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-III
The Additional Commissioner (System), Central Excise, Ahmedabad-III
The Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise, Kaii Division, Ahmedabad-III.
Guard file.

6. P.A